बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 179 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 01 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में दर्दनाक हादसा- द्वारका गोल्फ कोर्स के तालाब में तीन बच्चों की डूबकर मौत, इलाके में मचा हड़कंप

नई दिल्ली । दिल्ली द्वारका इलाके में तीन बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। घटना सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स की बताई जा रही है। यहां एक तालाब में तीन बच्चों के डूबने की सूचना मिली है। पुलिस और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को पानी से बाहर निकाला। यह घटना आज सुबह करीब 7:07 बजे हुई। सेक्टर 23 द्वारका पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अन्य सभी संबन्धित एजेंसियों को भी तत्काल सूचित किया गया। मौके पर पहुंचने पर लगभग 8 से 10 वर्ष की आयु के तीन बच्चे तालाब में डूबे हुए पाए गए।

शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस, ईडी की याचिका पर 22 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जांच एजेंसी ईडी की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी है.

जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा ने कहा पहले जारी किया गया नोटिस केजरीवाल तक पहुंचा ही नहीं था. अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था. जो उनके पास तक नहीं पहुंचा था. अब इस मामले वे फिर सुनवाई के लिए मौजूद हो सकते है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि पहले जारी किया गया नोटिस केजरीवाल तक पहुंचा ही नहीं था.. कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिस सर्व नहीं हुआ है.. इसलिए नया नोटिस जारी किया जा रहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने एजेंसी के समन मिलने के बावजूद जांच में शामिल होने से जानबूझकर इनकार किया. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने जांच से बचने के लिए बेवजह के बहाने बनाए. वहीं रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि ईडी यह साबित नहीं कर पाई कि समन सही तरीके से भेजे गए थे या केजरीवाल ने जानबूझकर उनकी अनदेखी की. कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईमेल के जरिए समन भेजने की प्रक्रिया कानून के मुताबिक साबित नहीं हो सकी. ईडी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गंभीर गलती है. क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समन जारी हुए थे और केजरीवाल को मिले भी थे.. फिर भी वे पेश नहीं हुए.इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की जरूरत और औचित्य से जुड़े मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज रखा है.

10वीं और 12वीं के परिणाम में बेटियों का दबदबा, 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास

दक्षिणी दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) ने बृहस्पतिवार को आइसीएसई कक्षा 10 और आइएससी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी कर दिए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हाईस्कूल व इंटर दोनों के परिणाम 99 प्रतिशत से अधिक रहे। इस बार आइसीएसई का परिणाम 99.18 और आइएससी का 99.13 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश 0.09 व 0.11 प्रतिशत अधिक है।

इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। आइसीएसई में 98.93 प्रतिशत छात्र, जबकि 99.46 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं।

यानी हाई स्कूल में छात्राओं का परिणाम 0.53 प्रतिशत अधिक रहा। वहीं दूसरी ओर आइएससी में 99.48 प्रतिशत छात्राओं के मुकाबले 98.81 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यानी इंटर

में भी छात्राओं का परिणाम छात्रों के मुकाबले 0.67 प्रतिशत ज्यादा रहा। इस वर्ष आइसीएससी कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि आइएससी कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से छह अप्रैल 2026 तक चली थीं। सीआईएससीई ने पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद कर दी थीं। पिछले वर्ष 2025 में सीआईएससीई ने 30 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। उस समय आइसीएसई का कुल पास प्रतिशत 99.09 और आइएससी का पास प्रतिशत 99.02 दर्ज किया गया था। बोर्ड के चीफ एक्जीक्यूटिव व सेक्रेटरी डॉ. जोसफ इमैनुएल ने बताया कि इस बार कक्षा 10 की परीक्षा में 1,37,503 छात्रों व 1,21,218 छात्राओं ने परीक्षा दी। इनमें से 1,36,032 छात्र जबकि 1,20,558 छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। वहीं बारहवीं में 54,118 छात्रों व 49,198 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 53,472 छात्र व 48,942 छात्राओं ने परीक्षा पास की। जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सीआईएससीई की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली।

सहकारिता आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 1 मई, 2026 को केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न प्रमुख पहलों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने, कोल्ड-चेन प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय डेयरी किसानों के लिए बाजार संपर्क को विस्तारित करने के उद्देश्य से विभिन्न डेयरी अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास का साक्षी बनेगा। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में सहकारी डेयरी संचालन के आधुनिकीकरण हेतु डिजिटल एवं संस्थागत पहलों का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री कारगिल में 10 टीएलपीडी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे तथा लेह में दही एवं पनीर उत्पादन सहित नई डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, दूध के भंडारण एवं परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए बल्क मिल्क कूलर प्रणाली का शुभारंभ किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में डिजिटल सशक्तीकरण के विजन को और मजबूत करते हुए, खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा किसानों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एंड्रॉयड-आधारित ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम एप्लिकेशन का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत एक मोबाइल दूध परीक्षण प्रयोगशाला को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा जमीनी स्तर पर डेयरी किसानों को सहयोग प्रदान करना है। प्रमुख हितधारकों के बीच डेयरी उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्धता और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होगी। सरकार के किसान कल्याण और सहकारी सशक्तीकरण पर विशेष जोर के अनुरूप, इस अवसर पर क्षेत्र के प्रगतिशील डेयरी किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह पहल सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने तथा देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कक्षाएं शुरू होने के बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं बंटीं किताबें, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने संबंधी अदालत के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के बाद भी पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ की दो-टूक, ऑपरेशन सिंदूर भारत की मर्जी से रुका, पाक आतंकवाद का वैश्विक केंद्र

नई दिल्ली । केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदुर को अपनी इच्छा और शर्तों पर रोकने का फैसला किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय देश लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था और किसी भी परिस्थिति से निपटने की क्षमता रखता था। दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति अब जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवादी हमलों पर केवल कूटनीतिक बयान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमले किए गए थे। हमने यह ऑपरेशन क्षमता की कमी के कारण नहीं रोका, बल्कि इसे अपनी शर्तों पर स्वेच्छा से रोका गया था।

राजनाथ सिंह बोले- भय बिन होय न प्रीति

राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा भय बिन होय न प्रीति यानी बिना भय के प्रेम संभव नहीं है। यही प्रतिरोध का मूल सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी यह बात लागू होती है कि मजबूत प्रतिरोध ही शांति और स्थिरता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस सिद्धांत का वास्तविक उदाहरण है,

जिसने दुनिया को भारत की नई रणनीतिक क्षमता का संदेश दिया।

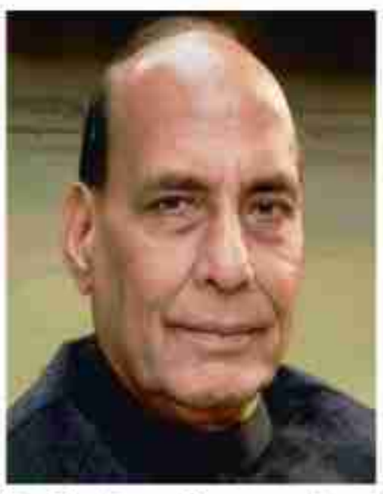

लंबे युद्ध की तैयारी और मजबूत सैन्य क्षमता

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की सैन्य क्षमता लगातार मजबूत हुई है और जरूरत पड़ने पर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी से प्रभावित नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने बताया कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर मात्र 72 घंटे में पूरा हुआ हो, लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी।

पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने लगातार आतंकवाद का समर्थन किया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में आजादी मिली थी। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। वहीं, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बन गया है। भारत का सैन्य औद्योगिक परिसर युद्धकाल में भी तेजी से आपूर्ति के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवाद केवल ऑपरेशनल नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर भी फैलता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की राजनीतिक और वैचारिक जड़ें ही उसकी असली ताकत हैं और इन्हें खत्म करना जरूरी है।

भारत की सैन्य क्षमता और स्वदेशी हथियारों पर भरोसा

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत की सैन्य ताकत में उसकी सर्ज क्षमता और स्टोरेज क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही स्वदेशी हथियारों की बढ़ती विश्वसनीयता ने भारत की प्रतिरोध क्षमता को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यही सभी तत्व मिलकर भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।

बातचीत के बाद हुआ था संघर्ष विराम

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में भारत ने भी सख्त कार्रवाई की। बाद में 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी।

स्वस्थ बचपन, सुरक्षित भविष्य

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना प्रदेश के नौनिहालों के समग्र विकास की दिशा में एक दूरदर्शी और जनोपयोगी पहल के रूप में स्थापित हुई है। इस योजना का उद्देश्य केवल ब'चों को भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें कुपोषण से मुक्त कर स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित नागरिक बनाना है। विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के ब'चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों तथा भारत सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। केंद्र सरकार द्वारा प्री-प्राइमरी स्तर के ब'चों को भी पोषण योजना के दायरे में लाने के निर्णय के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों तक विस्तारित किया। प्रदेश सरकार ने 12 अक्टूबर 2023 से प्रदेश में इस व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से लागू किया गया है। 24 नवंबर 2023 को अयोध्या से प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे बाल पोषण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1.90 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिससे लाखों ब'चों को प्रतिदिन लाभ मिल रहा है। यह पहल न केवल पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। ब'चों को प्रतिदिन प्रोटीन और कैलोरी युक्त संतुलित भोजन मिलने से उनके शारीरिक विकास में सुधार हुआ है। कुपोषण के स्तर में कमी आई है, वहीं एनीमिया (खून की कमी) जैसी समस्याओं में भी गिरावट दर्ज की गई है। ब'चों के वजन और ऊंचाई में सुधार के साथ-साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जो उनके उ'वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस योजना का प्रभाव उल्लेखनीय है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ब'चों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई है। जब ब'चों को ताजा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, तो वे नियमित रूप से केंद्रों पर आते हैं, जिससे उनकी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होती है और स्कूल जाने की आदत विकसित होती है। प्रदेश ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक सुदृढ़ और व्यावहारिक मॉडल अपनाया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की दूरी प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर के भीतर है, वहां विद्यालय की रसोई का उपयोग कर भोजन तैयार किया जाता है और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा ब'चों तक पहुंचाया जाता है। वहीं, दूरस्थ केंद्रों पर सहायिकाओं द्वारा ही भोजन तैयार किया जाता है। भोजन की गुणवत्ता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताहवार मेनू निर्धारित किया गया है, जिसमें दाल-चावल, रोटी-सब्जी, तहरी और खिचड़ी जैसे पौष्टिक व्यंजन शामिल हैं। यह न केवल ब'चों को संतुलित आहार प्रदान करता है, बल्कि उनके स्वाद और रुचि का भी ध्यान रखता है। साथ ही भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देकर उनकी भूमिका को भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संचालित यह योजना उत्तर प्रदेश के ब'चों के बेहतर भविष्य की आधारशिला रख रही है। यह पहल न केवल पोषण सुधार का माध्यम है, बल्कि एक सशक्त, स्वस्थ और शिक्षित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

सेवा, समर्पण और बदलाव की मिसाल बना आंगनबाड़ी केन्द्र

जनपद मिर्जापुर के ग्राम चांदलेवा कला का आंगनबाड़ी केन्द्र आज उस स'चे ज'बे का नाम बन चुका है, जो बिना किसी दिखावे के समाज में गहरा बदलाव लाया है। इस केन्द्र के ब'चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार आया है। पूरे गांव में जागरूकता की एक मजबूत नींव भी खड़ी हुई है। 1185 की जनसंख्या वाले इस गांव में यह आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में स्थित है। इस केन्द्र पर 0 से 06 माह तक के 09 शिशु, 07 माह से 03 वर्ष तक के 36 बच्चे, 03 से 06 वर्ष तक के 47 बच्चे, 06 गर्भवती महिलाएं और 09 धात्री माताएं पंजीकृत हैं, जिनकी देखभाल और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री पूरी तत्परता से निभा रही हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्री नियमित रूप से गृह भ्रमण करती हैं, प्रत्येक परिवार से संवाद स्थापित करती हैं और माताओं को ब'चों के सही पोषण, समय पर टीकाकरण, स्व'छता और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से संतुलित आहार, प्रसव पूर्व तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है और ब'चे के जन्म के एक घंटे के भीतर ही स्तनपान कराने पर जोर दिया जाता है, जिससे नवजात को जीवन की सबसे पहली और जरूरी सुरक्षा मिल सके। ग्राम चांदलेवा कला आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों को लगातार देखभाल, सही पोषण और परिवार को मार्गदर्शन देकर सामान्य श्रेणी में लाया गया है। अब गांव में यह जागरूकता विकसित हो चुकी है कि 0 से 06 माह तक के बच्चों को केवल मां का दूध ही दिया जाए और 06 माह के बाद उन्हें पौष्टिक पूरक आहार दिया जाए। इस बदलाव ने ब'चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार किया है और कुपोषण की दर में कमी आई है। आंगनबाड़ी केन्द्र से स्वास्थ्य, पोषण और स्व'छता का संदेश पूरे गांव में फैल रहा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है और परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है।

जहां बुद्ध घर लौटते हैं

भारत के इतिहास में पहली बार तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष अपने स्थायी संरक्षण-स्थल से उस भूमि को आशीर्वाद देने निकले हैं जिसने सदियों की कठिनाइयों, ऊंचाइयों और आस्था के बीच धर्म को जीवित रखा। यह एक सभ्यता का अपने आप को नमन है। किसी राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब इतिहास केवल खुद को दोहराता नहीं बल्कि और गहरा हो जाता है। इस बुधवार, जब तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष इस पैमाने पर सार्वजनिक श्रद्धा के साथ पहली बार भारत में लद्दाख की धरती पर उतरेंगे तो मैं खुद को सरकारी भाषा की ओर नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी चीज की ओर (श्रद्धा की ओर) मुड़ते हुए पाता हूं। सदियों से लद्दाख ने यह ज्योति संजोए रखी है। उन क्रूर सर्दियों में जो नदियों को जमा देती हैं, उन भू-राजनीतिक दबावों में जो मजबूत से मजबूत आत्माओं को भी आजमाते हैं, ऊंचाई की एकाकी दुनिया में और दूर-दराज के दर्रों की कठिनाइयों के बीच-लद्दाख के लोगों ने धर्म को ऐसी निष्ठा से जीवित रखा है जो हर संस्था और हर सरकार को नत-मस्तक कर दे। तो यह बिल्कुल उचित है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सार्वजनिक प्रदर्शनी किसी महानगर के वातानुकूलित संग्रहालय में नहीं, बल्कि यहां (दुनिया की छत पर) हो रहा है, जहां आस्था ही जीवन की बनावट है। तथागत के पवित्र अवशेषों की इस पावन प्रदर्शनी का आधिकारिक नाम भी एक घोषणा है- =संघर्ष के समय में शांति।= एक ऐसी दुनिया में जो युद्ध, विभाजन और बढ़ती दुश्मनी से जूझ रही है, ये शब्द उस सोच को चुनौती देते है जो संघर्ष को अनिवार्य मानती है, शक्ति को आक्रामकता से जोड़ती है, और अनिश्चितता का एकमात्र उत्तर बल में देखती है। बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले इस चुनौती का जवाब दिया था। हम उनकी भौतिक उपस्थिति को वापस ला रहे हैं ताकि दुनिया को याद दिला सकें, वह उत्तर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष जिन्हें अत्यंत पवित्रता के साथ संरक्षित किया गया है पहली बार अपने स्थायी संरक्षण-स्थल से बाहर निकलकर इस पैमाने पर भारतीय भूमि पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक विशेष विमान में वे 29 अप्रैल को लेह पहुंचा और पंद्रह दिनों तक (1 से 15 मई तक) शुभ 2569वीं वैसाख बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर से आरंभ होकर, दुनियाभर के श्रद्धालुओं, भिक्षुओं, विद्वानों और तीर्थयात्रियों के लिए यह प्रदर्शनी सुलभ रहेगी। स्थान भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, ऐतिहासिक लेह पैलेस का धर्म केंद्र, और जीवे-त्सल का शिक्षण स्थल वही पवित्र भूमि जहां परमपावन दलाई लामा ने अपनी शिक्षाएं दी हैं। अवशेष केवल लेह तक सीमित नहीं रहेंगे। 11 और 12 मई के बीच वे सुदूर जांस्कर घाटी की यात्रा करेंगे। उस समुदाय तक बुद्ध की कृपा पहुंचाने के लिए, जिनकी बौद्ध परंपराएं उनके परिदृश्य की खाइयों जितनी गहरी हैं। यह भारत की आत्मा, उसकी सभ्यता और उस शाश्वत संदेश का उत्सव है जो वह एक टूटती हुई दुनिया को देती है।= यह भूमि जिसने ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। यह समझने के लिए कि लद्दाख इस अवसर के लिए सही घर क्यों है, पहले लद्दाख को समझना होगा। यह केवल मठों और पहाड़ों का एक नाटकीय परिदृश्य नहीं है, चाहे वह परिदृश्य कितना भी मनोरम हो। यह धर्म का एक जीवित विश्वविद्यालय है। हेमिस मठ की शांत ऊंचाइयों से जिसका वार्षिक उत्सव समूचे हिमालयी संसार से तीर्थयात्रियों को खींचता है। अलची के प्राचीन भित्तिचित्रों तक, जो 10वीं सदी में बने और आज भी भक्ति की प्रतिभा से जीवंत हैं; दिस्कित की विशाल मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा से जो श्योक नदी की ओर अनंत करुणा की दृष्टि से देखती है थिकसे के बहुस्तरीय ज्ञान तक, जिसकी तुलना अक्सर तिब्बत के महान मठों से की जाती है लद्दाख हजार वर्षों से अधिक समय से बौद्ध दर्शन, कला, पांडुलिपि परंपरा और जीवंत साधना के सबसे असाधारण भंडारों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिकता के एक जीवंत केंद्र के रूप में निरंतर वर्णित किया है। उन्होंने लद्दाख के लोगों की लचीलेपन और देशभक्ति की। विशेषकर कठिन सीमा परिस्थितियों अक्सर बात की है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को राष्ट्रीय संकल्प और एकता से जोड़ते हुए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में विकास उसकी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ चलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है= लद्दाख न केवल अत्यंत रणनीतिक महत्व की भूमि है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं का एक जीवंत केंद्र भी है। पवित्र अवशेषों की यह यात्रा एक आध्यात्मिक आशीर्वाद भी है और बौद्ध विरासत को संजोने में लद्दाख की सदियों पुरानी भूमिका, तथा राष्ट्र की सेवा में यहां के लोगों के साहस और समर्पण की पहचान भी। अहिंसा, करुणा और आंतरिक जागृति पर बुद्ध की शिक्षाएं किसी एक समुदाय, संप्रदाय या परंपरा की संपत्ति नहीं हैं। चाहे वह गेलुग हो, द्रुकपा, काग्यु, या लद्दाख में फलती-फूलती कोई भी अन्य महान परंपरा, धर्म का सार एक ही रहता है= करुणा का, प्रज्ञा का, सद्भाव का मार्ग। प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में बड़ी संख्या में भिक्षुओं की एक विशाल बौद्ध जाप-सभा की योजना है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, और लद्दाख के स्थानीय संगठन-गोम्पा एसोसिएशन, बौद्ध एसोसिएशन और उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने उसी एकता के साथ मिलकर काम किया है जो स्वयं अवशेषों की शिक्षा में निहित है।

बुद्ध के आशीर्वाद से लद्दाख के हर घर में शांति आए, सभी समुदायों में सद्भाव हो और सभी

सम्पादकीय...

धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिखता जनपद मैनपुरीः सरकारी योजनाओं से बदली विरासत की तस्वीर

जनपद मैनपुरी सदियों से धार्मिक आस्था, प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की सुयोजित योजनाओं और वित्तीय निवेश ने इस ऐतिहासिक धरा को एक वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। 17 अप्रैल 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साझा प्रयासों से यहां के मंदिरों, आश्रमों और तीर्थस्थलों का न केवल जीर्णोद्धार हुआ है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। पर्यटन विकास की इस यात्रा का श्रीगणेश वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुआ, जब लगभग ?46 लाख की शुरुआती लागत से लालपुरी मंदिर महाराज मेला स्थल, खप्पर वाले बाबा सेवा आश्रम और मार्कण्डेय ऋषि आश्रम का विकास किया गया। यह भले ही एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसने विकास की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने स्व'छता और सौंदर्यीकरण के प्रति स्थानीय जनता में एक सकारात्मक विश्वास जगाया। इसके ठीक बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में धार्मिक सौहार्द की एक अनुपम मिसाल पेश करते हुए 48.84 लाख की लागत से करीमगंज स्थित मंदिर और खान बाबा की मजार का एक साथ विकास किया गया, जिसने समाज में एकता और समरसता का संदेश प्रवाहित किया। विकास का यह पहिया वित्तीय वर्ष 2022-23 में और तेजी से घूमा, जब सरकार ने 1181.91 लाख का भारी-भरकम बजट आवंटित कर रामलीला मैदान, मार्कण्डेय मंदिर बिधूना, ऋषि आश्रम औंछा और मयन ऋषि आश्रम का व्यापक कायाकल्प कराया। इन परियोजनाओं के तहत केवल मंदिरों की दीवारों को ही नहीं संवारा गया, बल्कि आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे रामलीला मैदान जैसे स्थलों को स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच प्राप्त हुआ। आधुनिकता और विस्तार के इसी क्रम को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ?1984 लाख खर्च किए गए, जिसके अंतर्गत ग्राम सहन में थिमेटिक गेट का निर्माण, शनिदेव मंदिर, सत्य कैलाश आश्रम नौरंगपुर, तुलसीदास मंदिर अछुपुर और प्राचीन घंटेश्वर जैसे स्थलों को व्यवस्थित और आधुनिक रूप दिया गया। करहल रामलीला मैदान के सुदृढ़ीकरण और बाउंड्रीवॉल निर्माण ने इन सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित और भव्य बनाया है।जनपद में पर्यटन की सबसे ऊंची छलांग वित्तीय वर्ष 2025-26 में देखने को मिली, जहां 3838.32 लाख की विशाल धनराशि से बजरंगबली हनुमान मंदिर खिरना खुर्द, नरसिंहधाम मंछना, वनखण्डेश्वर आश्रम भिरोर और सती माता मंदिर दौलतपुर सहित दर्जनों स्थलों का कायाकल्प किया गया। इन सभी परियोजनाओं में 'स्मार्ट टूरि'म' के तत्वों को शामिल करते हुए सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया और आकर्षक लाइटिंग व स्व'छता पर विशेष ध्यान दिया गया। संस्कृति विभाग के माध्यम से लगभग 24 करोड़ 61 लाख की लागत से प्रेक्षागृह एवं बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो मैनपुरी की सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नया आयाम देगा।

सावधान- प्लेसमेंट सर्विस या ठगी का नया व्यापार? प्लेसमेंट सेवाओं का मायाजाल

आज के दौर में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देती है। जब व्यक्ति को कहीं नौकरी की राह नहीं सूझती, तो वह तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश करता है। इसी मजबूरी और जरूरत का फायदा उठाने के लिए आज प्लेसमेंट सर्विसेज ने एक बड़े और संगठित व्यापार का रूप ले लिया है। आजकल हर गली-नुक्कड़ पर प्लेसमेंट सर्विस की दुकानें खुल गई हैं। ये केंद्र अक्सर मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं को अपना निशाना बनाते हैं। विडंबना देखिए कि इन धंधों को चलाने वाले खुद लोग अपने बच्चों को कभी इन रास्तों पर नहीं भेजते, लेकिन दूसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती।

लालच का वह फलों से लदा पेड़

कहते हैं कि अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। ठीक उसी तरह एक बेरोजगार को सिर्फ एक अदद नौकरी की तलाश होती है। प्लेसमेंट कंपनियां बेरोजगारों की इसी भूख को पहचानती हैं। वे उनके सामने नौकरी के अवसरों से लदा हुआ एक ऐसा फलों का पेड़ खड़ा कर देती हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति लोभ में पड़ जाए। उनकी चिकनी-चुपड़ी बातें ऐसी होती हैं कि अच्छे-भले समझदार इंसान भी उनके झांसे में आ जाते हैं।

फंसाने का अनोखा और मनोवैज्ञानिक तरीका- इन कंपनियों के जाल बिछाने का तरीका बेहद शातिर और चरणबद्ध होता है

1. रिज्यूमे अपलोड का चारा- शुरुआत होती है फ्री रिज्यूमे अपलोड करें और नौकरी पाएं के विज्ञापन से। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना बायोडाटा अपलोड करता है, वह उनकी रडार पर आ जाता है।
2. झूठी प्रशंसा का जाल- रिज्यूमे अपलोड होते ही आपके पास कॉल आता है। वे आपके अनुभव और काबिलियत की इतनी तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा कि आप ही उस पद के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। असल में यह प्रशंसा सिर्फ एक झांसा होती है ताकि आप उन पर भरोसा कर सकें।
3. जरूरत का विश्लेषण- ये कंपनियां आपके रिज्यूमे का गहराई से विश्लेषण करती हैं ताकि आपकी कमजोरी पकड़ी जा सके। वे देखते हैं कि आप कहां रहते हैं, आपकी पिछली सैलरी क्या थी और आप कितने जरूरतमंद हैं।
4. भावनाओं से खिलवाड़- अगर आप दूर नौकरी कर रहे हैं, तो वे कहेंगे– अरे! आप इतनी दूर जाते हैं? सारा पैसा तो आने-जाने में ही खत्म हो जाता होगा। हम आपको आपके घर के पास जॉब दिलाएंगे। अगर आपकी सैलरी कम है, तो वे कहेंगे– आपकी काबिलियत के हिसाब से आपका अप्रेजल सही नहीं हुआ है। हम आपको आपकी मनचाही सैलरी दिलवाएंगे।

मेंबरशिप के नाम पर वसूली

जब वे आपको पूरी तरह अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। वे कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल तो अच्छी है, बस इसमें कुछ प्रोफेशनल कमियां हैं जिन्हें हमारे एक्सपर्ट्स ठीक करेंगे। इसके नाम पर वे आपसे रजिस्ट्रेशन फीस, रिज्यूमे राइटिंग चार्जेस या प्रीमियम मेंबरशिप के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं।

हम दूसरों जैसे नहीं हैं

सबसे मजेदार बात तब होती है जब कोई ग्राहक उन पर शक करता है। उनके पास इसका भी रटा-रटाया जवाब होता है– सर, बाजार में बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं। हमारा काम जेन्युइन है। यह वाक्य उनके आत्मविश्वास को दिखाने का एक और तरीका होता है ताकि ग्राहक बिना डरे पैसे दे दे।

एक सबक

साल 2016 में पवन (बदला हुआ नाम) और उसके दोस्त सुनहरे भविष्य के सपने लेकर दिल्ली आए थे। उन्हें उत्तम नगर, द्वारका और गुरुग्राम जैसे इलाकों में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जालसाजों ने इस तरह का माहौल बनाया कि युवाओं को सब कुछ सच लगा। यहाँ तक कि फर्जी सरकारी कंपनी का ऑफर लेटर भी मिल कर दिया गया। भरोसे की आड़ में पवन से 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक ऐंठ लिए गए। आज भी वह न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका कीमती समय और पैसा बर्बाद हो चुका है।

सिस्टम और जवाबदेही पर बड़े सवाल

जैसा कि आपने सही पूछा है, आखिर इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति कौन देता है? क्या प्रशासन को इनसे निम्नलिखित सवाल नहीं पूछने चाहिए-

1. अनुभव का प्रमाण- इन्होंने अब तक कितने लोगों को वास्तव में नौकरी दिलवाई है?
2. विशेषज्ञता- क्या ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जिसकी नौकरियां ये बांट रहे हैं?
3. पारदर्शिता- क्या इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड या ऑडिट रिपोर्ट है?

ये सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट (नौकरी) को ऐसे पेश करते हैं जैसे 10 दिन में ही आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन हकीकत में यह केवल एक प्लेसमेंट बिजनेस है, सर्विस नहीं।

सुधार के लिए आवश्यक कदम

सख्त नियम- प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए पंजीकरण के नियम बेहद कड़े होने चाहिए।

रिफंड पॉलिसी- यदि कोई एजेंसी नौकरी दिलवाने में असमर्थ रहती है, तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा पैसा (ब्याज सहित) वापस करने का कानूनी नियम होना चाहिए।

कठोर दंड - पवन जैसे मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए ताकि दोषियों पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान हो।

अतत- किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को पैसा देने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें। नौकरी पाने की चाहत में अपनी मेहनत की कमाई इन ठगों को न दें। याद रखें, जो आपको घर बैठे रातों-रात आपकी उम्मीद से दोगुनी सैलरी का सपना दिखाए, समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है।

'मज़दूरों और बौद्धिकों की गिरफ़्तारी असहमति की आवाज़

मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति मजदूरों और वंचितों के अधिकारों की बात करता है, उसे बदनाम और दमन का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों को साजिशकर्ता कहा जा रहा है, वे दरअसल मजदूरों के बीच शांति बनाए रखने और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया ने कहा कि मजदूर अपने जीने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी खराब जीवन परिस्थितियों ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि चार नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद यूनियन बनाना और विरोध करना लगभग असंभव बना दिया गया है, और ऐसे में मजदूरों का यह आंदोलन पूरी तरह जायज है।

मुकुंद झा

देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सत्यम वर्मा रिहाई मंच द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पत्रकार, अनुवादक और जनबुद्धिजीवी सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। मंच ने इसे पूरी तरह अवैध, मनगढ़ंत और असहमति की आवाज़ को कुचलने की कोशिश करार दिया। मंगलवार को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के कई प्रमुख बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और लेखक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सत्यम वर्मा समेत अन्य गिरफ्तार लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंच की संयोजक कविता कृष्णपल्लवी ने विस्तार से बताया कि सत्यम वर्मा, जो 'भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज़' किताब के संपादक और कई विश्व प्रसिद्ध कृतियों के अनुवादक रहे हैं, को नोएडा के मजदूर आंदोलन से जुड़े एक हिंसा मामले में झूठा फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्यम का न तो कभी नोएडा से कोई प्रत्यक्ष संबंध रहा और न ही वे वहां के मजदूरों या कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे। इसके बावजूद उन्हें साजिश का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया गया। कविता कृष्णपल्लवी ने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी दरअसल सरकार और प्रशासन द्वारा एक मुखर आलोचनात्मक आवाज़ को खामोश करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सत्यम वर्मा लगातार जन मुद्दों, मजदूरों के सवालों और सरकारी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, और यही उनकी गिरफ्तारी का असली कारण है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए बताया कि 11 अप्रैल से ही पुलिस ने बिना किसी नोटिस या वारंट के सत्यम वर्मा और उनके साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। 13 अप्रैल को सत्यम वर्मा, कवयित्री कात्यायनी और पत्रकार संजय श्रीवास्तव को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। 17 अप्रैल को पुलिस ने 'जनचेतना' परिसर में एक मंजिल के लिए वारंट होने के बावजूद पूरे परिसर की तलाशी ली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताबें और निजी डायरी जब्त कर लीं, और इसके लिए कोई वैधानिक जब्ती सूची (सीज़र मेमो) भी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सत्यम वर्मा को बिना किसी ठोस आधार के उठाया गया, उन्हें जीवन रक्षक दवाइयों से वंचित रखा गया और उनके कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया। उन्हें दो दिन की गैरकानूनी हिरासत के बाद ही नोएडा की अदालत में पेश किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि उन सभी प्रगतिशील और जनपक्षीय आवाज़ों पर हमला है जो मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए बोलती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूर आंदोलनों से डरी हुई है और इसलिए ऐसे बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है जो इन आंदोलनों के साथ खड़े होते हैं। विनीत तिवारी ने कलाकारों, लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस दमन के खिलाफ आवाज़ उठाएं और सत्यम वर्मा समेत सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि दमन का इतिहास जितना पुराना है, प्रतिरोध की परंपरा भी उतनी ही मजबूत रही है और इसे जारी रखना होगा।

पीयूसीएल की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने भी इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने विशेष रूप से डी.के. बसु गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए कहा कि गिरफ्तारियों के दौरान जिन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कि पीयूसीएल इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने उठाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। कविता श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पुलिस अब तक यह भी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि नोएडा के मजदूर आंदोलन के दौरान कितने मजदूरों को हिरासत में लिया गया है, जो प्रशासन की अपारदर्शिता को दर्शाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति मजदूरों और वंचितों के अधिकारों की बात करता है, उसे बदनाम और दमन का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों को साजिशकर्ता कहा जा रहा है, वे दरअसल मजदूरों के बीच शांति बनाए रखने और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया ने कहा कि मजदूर अपने जीने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी खराब जीवन परिस्थितियों ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि चार नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद यूनियन बनाना और विरोध करना लगभग असंभव बना दिया गया है, और ऐसे में मजदूरों का यह आंदोलन पूरी तरह जायज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन सामाजिक कार्यकर्ताओं को मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता बताकर वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन करता था।

गिरफ्तार आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद ने बताया कि उनके भाई समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भी अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया और हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया कि जिन लोगों को साजिशकर्ता बताया जा रहा है, वे लगातार मजदूरों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की अपील कर रहे थे। केशव आनंद ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य यह भी दिखाते हैं कि हिंसा भड़काने में पुलिस की भूमिका रही, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यधारा की मीडिया इस सच्चाई को क्यों नजरअंदाज कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कविता कृष्णपल्लवी ने सभी पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और नागरिकों से अपील की कि वे सच और न्याय के पक्ष में खड़े हों और इस तरह की अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या देश में असहमति की आवाज़ों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह मामला केवल सत्यम वर्मा या अन्य छह लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर एक व्यापक हमला है, जिसका विरोध जरूरी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38862)

डीजल के लिए हाहाकार, पिकअप पर शव लेकर घंटों इंतजार

महराजगंज।

दूसरी गाड़ी से डीजल निकालकर पिकअप में भरा गया, पंप पर काफी देर बाद भी नहीं मिल सका डीजल

जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। डीजल के लिए हाहाकार मचा है। अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जा रहे पिकअप में डीजल भरवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन डीजल नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने दूसरी गाड़ी से डीजल निकालकर पिकअप में भरा तो शव लेकर पिकअप रवाना हुआ। पेट्रोल पंप में शव लेकर खड़े पिकअप का वीडियो भी शोसल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी ओर से दावा किया जा रहा है की उसी पंप में रात में तेल दिया जा रहा है। निचलौल थाना क्षेत्र के सिधावे पेट्रोल पंप पर पिकअप शव लेकर पहुंचा। पिछे एक ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी। उसमें भी डीजल भरवाना था। सिधावे गांव के रामेश्वर के छोटे सर्वेश गुप्ता की मौत हो गई थी। घर के लोग शव लेकर अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। पिकअप में तेल समाप्त होने पर गांव के बाहर पेट्रोल पंप में गाड़ी लेकर जाने के बाद घंटो इंतजार करना पड़ा। पंप के कर्मियों ने कहा की तेल अभी थोड़ी देर में मिलेगा। मृतक के परिजन इंतजार करते रहे। उनको कुछ सुझ नहीं रहा था। लोग कर्मियों ने अनुरोध

किए की तेल जल्दी दिया जाय, लेकिन किसी ने उनकी बातों को नहीं सुनी। अंतिम संस्कार करने में देरी होता देखकर लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। दूसरी गाड़ी से डीजल निकालकर पिकअप में भरा गया। इसमें बाद शव लेकर वाहन रवाना हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बनाकर शोसल मीडिया में वायरल कर दिया है। रामेश्वर कहते हैं कि इन दिनों समस्या काफी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल के लिए सभी को परेशान हो रही है। पंप पर इतनी भीड़ जुट जा रही है की घंटों इंतजार करने के बाद तेल नहीं मिल रहा है। पंप पर तेल आते ही कुछ ही देर में समाप्त हो रहा है।

भाई का शव लेकर जाने के दौरान डीजल समाप्त होने के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों ने तेल देना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि दावा किया जा रहा है की सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में पंप से लेकर गैस एजेंसी तक लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। परेशानी बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

आधी रात को पेट्रोल पंप से वितरित हो रहा था तेल

सिधावे पेट्रोल पंप पर एक ओर तेल नहीं मिला। दूसरी ओर आधी रात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोगों को पंप से तेल दिया जा रहा है। कर्मी लोगों से बात कर रहे हैं की जरूरत होने पर आ जाया करिए, यहां तेल मिल जाएगा। दिन में परेशानी होती है। वायरल वीडियो के माध्यम से दावा किया जा रहा है की अधिक मूल्य लेकर रात में तेल दिया जाता है।

दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी

महराजगंज। जनपद में घरेलू गैस की सुचारु आपूर्ति, गैस की कालाबाजारी व अवैध भंडारण पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कन्ट्रोल रूम की स्थापना की। कंट्रोल रूम का मोन- 8423675896 है, जिसपर आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलिंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। यदि कोई एजेंसी या व्यक्ति अवैध भंडारण या कालाबजारी में लिप्त पाया जाता है, तो आमजन उसकी शिकायत उपरोक्त नंबरों पर करें, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जनपद में पेट्रोल व डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता है। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलिंडर का वितरण सुचारू रूप से जारी है और अबतक कोई समस्या नहीं है।

15 जून तक हर हाल में पूरे हों बाढ़ बचाव कार्य -डीएम

कुशीनगर। जनपद में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी की बैठक आयोजित कर बाढ़ से निपटने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने बताया कि वर्तमान में 11 कार्य चल रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य 15 जून तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने अवर अभियंताओं को सक्रिय करते हुए प्रतिदिन कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा और स्वयं भी निरीक्षण करने की बात कही। जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर उन्हें पूरी तरह सक्रिय रखने तथा सभी संपर्क नंबर चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रेन सफाई कार्यों को चिन्हित कर विभागवार सूची तैयार करने और उसकी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में राजस्व, पूर्ति, चिकित्सा, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि, विद्युत, लोक निर्माण और शिक्षा विभागों द्वारा बाढ़ के दौरान किए जाने वाले कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी, वाइंट मजिस्ट्रेट, डीसी मनरेगा, जिला गन्ना अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

छह माह के मासूम की हत्या का खुलासा, पिता गिरफ्तार

कुशीनगर। तरयासुजान थाना क्षेत्र में छह माह के मासूम बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पारिवारिक विवाद के बीच अपने ही बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक थाना तरयासुजान में दर्ज मुकदमा संख्या 103/2026 के तहत आरोपी सलमान पुत्र रजाक, निवासी कामीपुर, थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई को बुधवार को तरयासुजान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ धारा 103(1), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सलमान अपनी पत्नी के बार-बार बिना बताए मायके चले जाने से नाराज था। 27 अप्रैल की रात वह नशे की हालत में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था। पत्नी के साथ वापस जाने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में आकर उसने अपने छह माह के बेटे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान, उपनिरीक्षक शशांक शेखर राय, कांस्टेबल विपिन पांडेय, कांस्टेबल गिरीश कुमार, आरक्षी जयप्रसाद यादव और आरक्षी विपिन कुमार राजभर शामिल रहे।

देवरिया में लोकतांत्रिक घेराबंदी- बरहज कूच से पहले पुलिसिया सख्ती, गजाला लारी समेत सपा के दिग्गज नेता हाउस अरेस्ट

देवरिया।

तहसील मुख्यालय पर भारी पीएसी तैनात, दर्जन भर थानों की फोर्स ने संभाली कमान

पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रही कार्रवाई को सपा ने बनाया ढाल, सरकार को जनविरोधी घोषित करने की तैयारी।

उत्तर प्रदेश की सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही वर्चस्व की जंग गुरुवार को देवरिया की सड़कों पर उस समय और तीखी हो गई, जब जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के बरहज तहसील घेराव कार्यक्रम को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बरहज विधानसभा के लक्ष्मीपुर और दुबौली ग्राम प्रधानों पर हुई कार्रवाई को एकतरफा करार देते हुए आंदोलन पर आमादा सपा के तेवरों से घबराई पुलिस ने आधी रात के बाद ही पूरे जनपद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सलेमपुर स्थित लारी हाउस की किलेबंदी करते हुए पुलिस ने पूर्व विधायक व सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य फसीह मंजर गजाला लारी को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया।

लक्ष्मीपुर कांड- न्याय की मांग या सियासत की बिसात

दरअसल, यह पूरा उबाल बीते 5 अप्रैल को ग्राम लक्ष्मीपुर में सड़क निर्माण विवाद के दौरान अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ है। इस मामले में पुलिस ने लक्ष्मीपुर प्रधान राजेश यादव और दुबौली प्रधान गामा यादव समेत 5 नामजद व 8 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन उप जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी को पहले ही निलंबित

किया जा चुका है। जहां एक ओर अधिवक्ता न्याय के लिए डटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी इन प्रधानों को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित कार्रवाई कह रही है। इसी के विरोध में गुरुवार को बरहज तहसील के घेराव का आह्वान किया गया था।

जुल्म की मीआद के दिन थोड़े हैं - गजाला लारी

नजरबंदी के बीच से पूर्व विधायक गजाला लारी के तेवर और अधिक तल्ख नजर आए। उन्होंने फैज अहमद फैज की कालजयी पंक्तियों के जरिए हुंकार भरी– लेकिन अब जुल्म की मीआद के दिन थोड़े हैं, इक ज़रा सब्र कि फरियाद के दिन थोड़े हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार सच का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि पुलिस उनके शरीर को तो कैद कर सकती है, लेकिन उनके आजाद खयालों और संघर्ष के जबे पर पहरा नहीं लगा सकती। गजाला लारी ने कहा कि सरकार चाहे उन्हें जेल भेज दे या घर में कैद रखे, निर्दोषों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई किसी भी कीमत पर जारी रहेगी और जनता के हक की आवाज दबेगी नहीं।

छावनी बना बरहज, परिंदा भी पर नहीं मार सका

प्रशासन ने सपा के आंदोलन को निष्प्रभावी करने के लिए बरहज तहसील परिसर को पुलिस किले में तब्दील कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी राजेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में बरहज, भलुअनी, सलेमपुर, मदनपुर, भाटपाररानी, मझल, गौरीबाजार और खुखुंदू समेत दर्जन भर थानों की पुलिस और दो प्लाटून पीएसी के जवानों ने प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी कर दी। किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पुलिस ने सपा के बरहज कूच के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव, पूर्व रायसभा सांसद कनकलता सिंह, पूर्व विधायक स्वामीनाथ, पूर्व जिलाध्यक्ष गेना लाल यादव, तेज प्रकाश जायसवाल, परमहंस यादव, विजय रावत, बेचू लाल यादव, वीरेंद्र चौधरी, संतोष यादव और मनोज यादव समेत करीब दो दर्जन दिग्गज पदाधिकारियों को उनके घरों में ही बंधक बना लिया। सपा नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना लोकतंत्र की हत्या है और यह साबित करता है कि सरकार सचाई का सामना करने से डरी हुई है। देर शाम तक जिले में तनावपूर्ण शांति बनी रही, लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई ने आगामी सियासी संघर्ष की नई इबारत लिख दी है।

बिना कोचिंग के लक्ष्मी ने रचा कीर्तिमान

आईएससी 12वीं में 95.75 फीसदी अंक, ग्रामीण छात्रों के लिए बनी प्रेरणा

भटनी देवरिया।

भटनी ब्लॉक अंतर्गत नोनापार गांव की प्रतिभाशाली छात्रा लक्ष्मी ने कक्षा 12 आईएससी बोर्ड की परीक्षा में 95.75 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि लक्ष्मी ने बिना किसी कोचिंग के अपनी मेहनत, लगन और निरंतरता के दम पर यह मुकाम हासिल किया। ग्रामीण परिवेश में रहकर सीमित संसाधनों के बावजूद लक्ष्मी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो सफलता जरूर मिलती है। इससे पहले भी उन्होंने हाईस्कूल परीक्षा में 94 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। लक्ष्मी की पूरी शिक्षा लिटिल फ्लावर स्कूल से हुई है।

इंटरमीडिएट आईएससी परीक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लक्ष्मी की इस उपलब्धि से नोनापार गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। लक्ष्मी आज ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों, विशेषकर बेटियों के लिए एक आदर्श बनकर उभरी हैं।

भटनी-गोपलापुर मोड़ पर भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

भटनी देवरिया।

क्षेत्र के भटनी-गोपलापुर मोड़ के समीप बृहस्पतिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि स्प्लेंडर प्लस बाइक (नंबर बी.आर.BR 28 ए.जे. 9897) तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में शशि पटेल 23 वर्ष, पुत्र दरोगा, निवासी जिला गोपालगंज, सिवान थाना क्षेत्र के ताली विशुनपुरा बाजार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे अमन 24 वर्ष, पुत्र लालशाह पटेल, निवासी चकउर फकीर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और वाहन सीधे पेड़ से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना मिलते ही भटनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल युवक का उपचार जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट बोला-रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं- केंद्र से कहा- अपने कानून में बदलाव करें, अभी 6 महीने तक गर्भपात का नियम

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, 'कानून ऐसा होना चाहिए, जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब सात महीने प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ AIIMS ने याचिका लगाई थी। AIIMS ने कहा था कि 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में भ्रूण एक जीव का आकार ले चुका होता है और इस स्टेज पर अबॉर्शन सफल नहीं हो सकता। AIIMS की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग प्रेग्नेंसी जारी रखती है तो उसे हर दिन मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। अभी भारत का कानून रेप मामलों में 6 महीने तक की प्रेग्नेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है। 24 अप्रैल को सुनवाई में विक्टिम के वकील ने कहा कि इस प्रेग्नेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग में पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव के संकेत दिख रहे हैं। वह आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लड़की और उसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। उन्होंने नाबालिग को आर्थिक मदद की पेशकश भी की। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि हम महिलाओं को अबॉर्शन के बजाय आर्थिक मदद या गोद लेने जैसे विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, 'किसी महिला, खासकर नाबालिग को इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी पूरी करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना जरूरी है।' कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। इसलिए गोद देने का विकल्प किसी महिला को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालतें अनचाही गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देंगी तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटर्स का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतों को यह देखना चाहिए कि गर्भवती महिला के हित में क्या बेहतर है, खासकर तब जब गर्भ स्पष्ट रूप से अनचाहा हो। अंत में कोर्ट ने नाबालिग का AIIMS दिल्ली में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया।

युवाओं के आशियाने पुलिस राज में बदले गए; लद्दाख पर बोले राहुल- लोकतांत्रिक अधिकार भी कुचले गए

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़े मसले पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, लद्दाख के युवाओं ने मुझे बताया कि किस तरह उनके खूबसूरत आशियाने को एक पुलिस राज में बदल दिया गया है। उनकी आवाज दबा दी गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया है और उनकी जमीन और नाजुक पर्यावरण को मोदी जी के अरबपति मित्रों के हवाले किया जा रहा है। राहुल ने लिखा, लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं। वो रोजगार और उद्योग चाहते हैं, मगर ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। आशा है कि अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री इस सच्चाई को समझ पाएं।

ऑटो रिक्शा को डंफर ने मारी टक्कर, सीआईएसएफ जवान समेत तीन की दर्दनाक मौत

खगड़िया। बिहार में खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह ऑटो रिक्शा और डंफर के बीच हुई टक्कर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीआईएसएफ जवान बिपिन कुमार अपनी पत्नी दीपमाला चौरसिया के साथ बड़ी मालिया गांव से मानसी स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिये ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। इस दौरान गौछारी पेट्रोल पंप के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर ऑटो रिक्शा और डंफर के बीच टक्कर हो गयी। इस दुर्घटना में आईएसएफ के जवान बिपिन कुमार, उनकी पत्नी दीपमाला चौरसिया और ऑटो रिक्शा चालक कैलाश मुनि की मौके पर ही मौत हो

दिल्ली-नोएडा में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश, गाजियाबाद में गिरे ओले

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है. दोपहर तक जहां उमस और गर्मी से बुरा हाल था वहीं अब तेज आंधी ने मौसम बदल दिया है. कुछ इलाकों में बारिश हो रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ओले पड़ रहे हैं. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में अगले तीन घंटे में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश पड़ रही है. कुछ इलाकों में ओले पड़ने की भी खबर है. अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. राजधानी के सफदरजंग में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं आईएमडी ने दिन में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया. अन्य मौसम निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 23.6 डिग्री सेल्सियस, रिज में 25 डिग्री सेल्सियस और अयानगर में 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं. गाजियाबाद में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी. जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी परेशान थे गुरुवार को दोपहर करीब 3:00 बजे अचानक से काले बादल छा गए इसके साथ ही गाजियाबाद के कुछ इलाकों में बारिश होने लगी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं ऐसे में घर से निकले लोगों को दिक्कत तो हो रही है लेकिन मौसम में बदलाव के चलते वह भी आराम महसूस कर रहे हैं. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं और पूर्वानुमानों से संकेत मिले हैं कि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली (नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी) और एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन AF स्टेशन) के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश/बूंदाबांदी के साथ हल्की गरज और बिजली चमकने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा हरियाणा के राजौंद, पानीपत और गन्नौर वहीं यूपी के कांधला, बड़ौत में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने के आसार है.

तेजस्वी का सरकार पर बड़ा हमला- 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री, फिर भी दिशाहीन है बिहार सरकार

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छह महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार से कई सवाल पूछे और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद छह महीने के भीतर राज्य ने दो मुख्यमंत्री देख लिए हैं और सरकार के कार्यकाल का पहले साल का 46.03 प्रतिशत समय व्यर्थ हो चुका है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि लगभग 50प्रतिशत समय बीत जाने के बावजूद सरकार की प्राथमिकताएं और नीतियां तय नहीं हो सकी हैं।

उन्होंने कहा कि अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श तथा विचार के निर्णय लिए जा रहे हैं। राजद नेता ने दावा किया कि सत्ता के लोभ में राजग नेताओं ने नैतिकता और लोकलाज की मर्यादाएं त्याग दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में पांच बार तथा 12 वर्षों में 10 बार सरकार का गठन और पुनर्गठन हुआ है। यादव ने आरोप लगाया कि बार-बार नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे बिहार दिशाहीन हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य आज बेलगाम नौकरशाही, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कमजोर कानून-व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। राजद नेता ने दावा किया कि नयी सरकार के गठन के छह महीने में ही प्रदेशवासी उदासीन हो चुके हैं और बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी तथा व्यापारी अब सरकार से निराश हैं। उन्होंने कहा, जो सरकार स्वयं अपने लिए समस्या है, वह जनता का समाधान क्या करेगी?

यूपी और बिहार में आंधी-बारिश से 18 मौतें

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग-अलग मौसम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पारा 40 से 46डिग्री के बीच रहा। हालांकि, आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान 2 से 3डिग्री तक घट भी गया। दिल्ली में दोपहर बाद ओले गिरे। उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश से 13 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 7 मौतें हुईं। वहीं, बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। पटना में आंधी से दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में पेड़ गिर गए। उत्तराखंड के मसूरी में गुरुवार को ओले गिरे। यूपी का बांदा लगातार दूसरे दिन 45.8डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान-मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40डिग्री से ज्यादा रहा। एमपी में भोपाल और सीधी सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहां पारा 43डिग्री से ज्यादा रहा।

तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की साझेदारी वाले गठबंधनों को मिलेगा बहुमत - खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी की साझेदारी वाले गठबंधनों के स्पष्ट बहुमत हासिल करने की बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि असम में नौ अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एग्जिट पोल के अनुमान से अधिक सीटें मिलेंगी। खरगे ने कहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में लड़ाई पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के तहत मतगणना चार मई को होगी। खरगे ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, कुछ जगहों पर एग्जिट पोल के नतीजे स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन कुछ परिणामों ने भ्रम की स्थिति पैदा की है। मेरा मानना है कि तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मैंने वहां के लोगों से बात की है। इसी तरह केरल में हमारे लोगों ने बताया है कि कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा, एग्जिट पोल में, असम में हमें अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं दी गई हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमें उससे अधिक सीटें मिलेंगी। पुडुचेरी में हमने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ी है। वहां भी हमें उम्मीदें हैं। वह कड़ा मुकाबला रहा है, कुछ दिन इंतजार करते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और आंतरिक सूचना के अनुसार मुकाबला कड़ा रहा है। खरगे ने कहा, हमारी जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस आगे है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने केंद्रीय बलों की तैनाती के जरिए दमन करने और डराने-धमकाने की कोशिश की, ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी जा सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए, पश्चिम बंगाल में हमारी शुरू से ही लड़ाई रही है। हमने वहां पहली बार अकेले चुनाव लड़ा है। हमारी लड़ाई पार्टी के हित और उसके विस्तार के लिए रही है। खरगे ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनावों के नतीजे पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। उन्होंने कहा, अभी तीन दिन बाकी हैं। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन इंतजार करें, तस्वीर साफ हो जाएगी। बुधवार को जारी कई एग्जिट पोल में असम में भाजपा की प्रचंड जीत और पश्चिम बंगाल में उसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिखायी गई है, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक के सत्ता में बने रहने तथा केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ की 10 साल बाद वापसी का अनुमान जताया गया है। हालांकि, कुछ सर्वेक्षणों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत और तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना भी जताई गई है। लगभग सभी एग्जिट पोल में पुडुचेरी में राजग सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है।

बस बहुत हुआ, पाकिस्तान से बोले फारूक अब्दुल्ला- जम्मू-कश्मीर में हिंसा खत्म करे

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हिंसा का चक्र समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया और अब पाकिस्तान को हिंसा का रास्ता छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग न मानना हिंसा को बढ़ावा देता है। फारूक अब्दुल्ला ने दिए एक साक्षात्कार में कहा कि दोनों देशों को शांति के तरीके खोजने चाहिए। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने इसे भाईचारे को फिर से जगाने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया। हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि पड़ोसी देश आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग शांतिप्रिय हैं और शांति चाहते हैं। अब्दुल्ला के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा अब उग्रवाद नहीं, बल्कि ड्रग्स का बढ़ता प्रकोप है। उन्होंने इस व्यापार में कुछ स्थानीय लोगों की संलिप्तता पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया ताकि कोई इसे जारी न रख सके। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर माता-पिता और नागरिक को एकजुट होना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है।

मां, माटी और मानुष की सरकार बना रहे हैं- 226 सीटें जीतेंगे- ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मां, माटी और मानुष की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी 226 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रॉन्ग रूम की दिन-रात रखवाली करने के लिए भी कहा है। बता दें कि सीएम ममता ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में मुख्यमंत्री ममता ने जनता को संबोधन करते हुए आभार जताया और चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम ममता ने कहा, बंगाल के मां, माटी, मानुष को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि इतनी धूप में और इतने अत्याचार झेलकर आप लोगों ने जिस हिसाब से वोट दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं अपने कर्मियों का भी आभार जताती हूं जिन्होंने तमाम अत्याचार को बर्दाश्त करके, ना सिर्फ सेंट्रल फोर्स बल्कि यहां के फोर्स का भी अत्याचार सहन करके अपने काम किया। सीएम ममता ने आगे कहा, मैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर लूं, काउंटिंग एरिया को छोड़कर कोई न जाए। यह भी ध्यान रखना है कि ईवीएम की काउंटिंग के बाद उसका डाटा कम्प्यूटर में सही लिखा जा रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के नंबर भाजपा में जोड़ दिए जाएं। उन्होंने कहा, भारत सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री-गृह मंत्री से लेकर 19 भाजपा शासित राज्यों के नेताओं ने बंगाल के लोगों को कब्जाने की कोशिश की। मैं यह बताती हूं कि मतदाता पेटी में वोट जब्त हो गए हैं। मैं बहुत निश्चित होकर बोल रही हूं कि जो टीवी पर दिख रहा है वो सब पैसों का खेल है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रही हूं कि 2026 में हम 226 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। लोगों ने जिस तरह वोट दिया है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा ने प्रेस के जरिये ये (एग्जिट पोल) कराया है। ये लोग ईडी, सीबीआई के जरिये धमकाते हैं। ममता ने कहा कि अमित शाह के सीधे निर्देश पर पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान केंद्रीय बल भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री-गृह मंत्री से लेकर 19 बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं ने बंगाल के लोगों को कब्जाने की कोशिश की।

पंजाब में लगेगा राष्ट्रपति शासन! कई आप विधायक भाजपा में जाएंगे -सुखजिंदर रंधावा

चंडीगढ़। गुरदासपुर से कांग्रेसी सांसद एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार संकट में है और आने वाले समय में सूबे में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आप के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं।

कांग्रेस का कोई सांसद- विधायक भाजपा में नहीं जा रहा

रंधावा ने स्पष्ट किया कि पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और उनके समेत चार कांग्रेसी सांसदों के भी भाजपा में संपर्क होने की अफवाह फैलाई गई थी मगर मैं विश्वास से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी मौजूद सांसद और विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी में उथल-पुथल की स्थिति जरूर चल रही है।

गद्दारों ने गद्दारों से गद्दारी की

रंधावा ने कहा कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। आप के राज्यसभा सांसदों को गद्दार कहने पर रंधावा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गद्दारों ने गद्दारों के साथ ही गद्दारी की है क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो पहले शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में थे और आज वे आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री और अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं। रंधावा ने कहा कि कांग्रेसियों को भाजपा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस के आला नेता पहले भाजपा में जा चुके हैं उनकी आज क्या स्थिति है वह सभी जानते हैं।

डीजीपी गौरव यादव को चुनौती

रंधावा ने प्रदेश के डीजीपी गौरव यादव को भी चुनौती देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पंजाब की कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। नशा तस्करों, गैंगस्टरों के बाद अब फिर से उग्रवाद मुखर होने लगा है। रेल ट्रैकों पर धमाके इसका ताजा उदाहरण हैं। पंजाब सरकार को इस गंभीर स्थिति में पंजाब पुलिस के नेतृत्व पर संज्ञान लेना होगा। सभी दलों को एकजुट होकर कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम करना होगा। पंजाब सरकार के विधानसभा सत्र के संदर्भ में रंधावा ने कहा कि यह सत्र मजदूरों के हितों की बात करने की आड़ में अपना सियासी लाभ लेने की कवायद है।

स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी-भाजपा में तकरार- भारी सुरक्षा बल तैनात; ममता भी पहुंचीं, ईसी बोला- कोई गड़बड़ नहीं

***स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी-भाजपा में तकरार**
*** भारी सुरक्षा बल तैनात; ममता भी पहुंचीं**
***स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना खत्म**

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कोलकाता में सियासी तनाव बढ़ गया है। शशि पांजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप के बाद चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता भी वहां पहुंच गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बाद में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और टीएमसी ने धरना भी खत्म कर दिया है। अब इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं।

क्या भाजपा और चुनाव आयोग कर रहे हैं मतपेटियों से छेड़छाड़?

टीएमसी नेताओं शशि पांजा और कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम के अंदर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि संबंधित पार्टी (टीएमसी) के प्रतिनिधियों के बिना ही मतपेटियां खोलने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप भाजपा और भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर सीधा लगाया गया है। नेताओं का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

स्ट्रांग रूम पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता गुरुवार को दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचीं। यह भवानीपुर सीट का काउंटिंग सेंटर है, जहां 29 अप्रैल को हुए मतदान की ईवीएम रखी गई है। ममता बनर्जी ने मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मौके का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बावजूद वह वहां पहुंचीं और देर तक अंदर मौजूद रहीं। इस दौरान कोलकाता मेयर और टीएमसी उम्मीदवार हकिम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वह उनसे नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने अधिकार के तहत अंदर गई हैं। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक टीएमसी वाहन को रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। उनका आरोप था कि वाहन में कुछ संदिग्ध सामान मौजूद है। एक

कार्यकर्ता ने कहा कि ममता बनर्जी के वाहन में कुछ लाया गया है, इसलिए उसे जाने नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में माहौल गरमा गया और दोनों दलों के समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति बन गई।

शशि पांजा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए क्या सवाल उठाए?

टीएमसी नेता शशि पांजा ने भी अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग से सीधा सवाल किया कि आखिर हमें वह सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है जो अंदर हो रहा है? पांजा ने कहा कि अगर अंदर सब कुछ सही हो रहा है, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बाहर क्यों रखा गया है? आगे उन्होंने कहा कि अंदर कौन लोग मौजूद हैं और क्या काम चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। रूम के भीतर जाने की अनुमति नहीं मिल रही और पूरी प्रक्रिया पर संदेह है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में खामियां हैं और कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। टीएमसी ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और निगरानी की मांग की है।

कुणाल घोष ने लाइव स्ट्रीमिंग का हवाला देकर क्या दावा किया?

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग के सीसीटीवी कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। घोष ने कहा कि आप चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग में साफ देख सकते हैं कि अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अंदर टीएमसी का एक भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है और उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। घोष के मुताबिक, जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, तो उनसे कहा गया कि वे अन्य उम्मीदवारों से बात करें। उन्होंने सवाल उठाया, हम दूसरे उम्मीदवारों की जिम्मेदारी क्यों लें? वहीं, घटनास्थल पर भारी सुरक्षाबल की तैनाती भी है।

विवाद पर भाजपा का जवाब, तपस रॉय बोले- अफवाह फैला रही टीएमसी

कोलकाता में स्ट्रांग रूम को लेकर जारी विवाद पर भाजपा नेता तपस रॉय ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा दो लोगों को स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए तैनात करेगी। रॉय ने आरोप लगाया कि टीएमसी अपनी हार की आशंका से अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि यहां तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।

विवाद पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

मामले पर चुनाव अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि परिसर में सात विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम मौजूद हैं, जिन्हें मतदान के बाद उम्मीदवारों, एजेंटों और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में सील किया गया था। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह करीब 5-15 बजे बंद किया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और लॉक हैं। परिसर में एक अलग स्ट्रांग रूम पोस्टल बैलेट के लिए भी बनाया गया है, जहां अलग-अलग क्षेत्रों के बैलेट रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की जानकारी पहले ही ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि बैलेट की छंटाई स्ट्रांग रूम के बाहर कॉरिडोर में की जा रही थी। साथ ही यह पूरी स्थिति टीएमसी नेताओं शशि पांजा और कुणाल घोष तथा भाजपा प्रतिनिधि को भी दिखा दी गई है।